

दिप्रिंट

<https://hindi.theprint.in/india/people-across-the-world-are-looking-towards-india-for-solutions-to-their-problems-himachal-pradesh-governor/611195/>

दुनियाभर में लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारत की ओर देख रहे हैं: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल

भाषा

8 October, 2023 05:20 pm IST

गांधीनगर, आठ अक्टूबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने रविवार को कहा कि दुनियाभर में लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारत की ओर देख रहे हैं क्योंकि विदेश में भारत के प्रति धारणा उसके मजबूत नेतृत्व तथा 'अमृतकाल' में विकसित राष्ट्र बनने के उसके लक्ष्य के कारण बदल गयी है।

'अमृत काल' वह शब्दावली है जिसे नरेन्द्र मोदी सरकार 2047 तक की अवधि के लिए अक्सर प्रयुक्त करती है और यह इस अवधि में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास करने की जरूरत है।

शुक्ला ने कहा, " आज दुनिया के लोग अपनी समस्याओं का समाधान भारत में ढूँढ रहे हैं। इसका मतलब है कि देश के मजबूत नेतृत्व के कारण (भारत के प्रति) दुनिया की धारणा में परिवर्तन आया है।"

Fullscreen

वह 'इंडिया थिंक काउंसिल' के साथ मिलकर 'इंटरप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट ऑफ इंडिया' द्वारा 'अमृतकाल का भारत' विषय पर आयोजित एक व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे।

अपने संबोधन में शुक्ला ने राजनीति के लिए जाति का मुद्दा उठाने के वास्ते 'राममनोहर लोहिया के अनुयायियों' पर निशाना भी साधा। उनका इशारा बिहार में जाति आधारित गणना कराये जाने के बाद विभिन्न विपक्षी दलों द्वारा की जा रही इस तरह के सर्वेक्षण की मांग की ओर था।

शुक्ला ने कहा, “ क्या कोई सोचता है कि कोई किस जाति से है? इस देश ने हमें महान समाजवादी डॉ. राम मनोहर लोहिया दिया। उन्होंने जातियों के बंधन को तोड़ने का आह्वान किया था।”

उन्होंने कहा कि समाजवादी होने के बावजूद लोहिया ने चित्रकूट में रामायण मेले का आयोजन किया था और संसद के लोगों को अयोध्या आने तथा भगवान राम के आदर्शों पर चलने की अपील की थी।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि उनके अनुयायी राजनीति की खातिर जाति के पीछे भाग रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अमृतकाल की पहचान तिरंगा का बढ़ता अभिमान है, लेकिन जब कोई आत्मगौरव की अपनी भावना प्रकट करता है तो लोग सोचते हैं कि वह सांप्रदायिक है।

सन 2002 के गोधरा दंगे का जिक्र करते हुए शुक्ला ने कहा कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री (नरेन्द्र मोदी) को जिम्मेदार ठहराया गया लेकिन शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए उन्हें बरी कर दिया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया।